

प्रेषक,

अनीता सिंह,

सचिव,

उ०प्र०शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग -२

लखनऊ: दिनांक २१ दिसम्बर, २००९

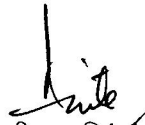
विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ के अंतर्गत विभागों में प्रत्येक माह में लम्बित / निस्तारित आवेदन पत्रों की स्थिति की सूचना प्राप्त करने विषयक।

महोदय,

कृपया मुख्य सचिव के अर्द्ध शासकीय पत्र सं०-१२३१/४३-२-२००८, दिनांक ०१ दिसंबर, २००८ तथा प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र सं० ३७१/४३-२-२००९, दिनांक १७ मार्च २००९ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ के अन्तर्गत प्राप्त लम्बित एवं निस्तारित आवेदन पत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए प्रत्येक माह की १० तारीख तक संकलित सूचना प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध कराने विषयक है।

२- माह नवम्बर, २००९ तक प्राप्त सूचनाओं की समीक्षा किये जाने पर यह पाया गया कि सचिवालय स्तर पर निर्धारित तिथि तक केवल दस विभागों द्वारा सूचनायें प्रेषित की गई हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि आपके विभाग के जन सूचना अधिकारियों द्वारा इसे गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। बहुधा यह भी प्रकाश में आया है कि विभागाध्यक्ष / मण्डल स्तरीय / जनपदीय कार्यालयों द्वारा सीधे सूचना प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रेषित की जाती है जिसके कारण सूचनाओं के संकलन में कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त सूचनायें निर्धारित तिथि, प्रत्येक माह की १० तारीख, के पश्चात प्राप्त होती हैं। कतिपय विभागों द्वारा त्रुटिपूर्ण सूचनायें प्रेषित की जाती हैं।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ के अन्तर्गत प्राप्त, लम्बित एवं निस्तारित आवेदन पत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुये प्रत्येक माह की १० तारीख तक संकलित सूचना निर्धारित प्रारूप में प्रशासनिक सुधार विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


(अनीता सिंह)
सचिव।